दैनिक जागरण

एकाग्रता की राह में बड़ी बाधा हमारे भीतर उठती अभिलाषाएं हैं

एक और एकतरफा चिट्ठी

असहमति की अनदेखी और भीड़ की हिंसा को लेकर 49 बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपनी जो चिंता जाहिर की वह नई नहीं है। इस तरह की चिट्ठियां पहले भी लिखी जा चुकी हैं। इतना ही नहीं असहिष्णुता बढ़ने का शोर मचाते हुए पुरस्कार भी वापस किए गए हैं और जनता से यह आग्रह भी किया गया है कि भाजपा को वोट न दें । इस तरह की चिट्ठियां लिखने वाले खुद को लिबरल यानी उदारवादी बताते हैं, लेकिन शायद वे खुद नहीं जानते कि उदारवाद क्या है? चूंकि ऐसे बुद्धिजीवी चतुराई से चुनिंदा मामलों का उल्लेख करते हुए अपनी एकतरफा सोच ही सामने रखते हैं इसलिए उनकी अपीलों का कोई असर नहीं होता। इस नई चिट्ठी का भी असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें केवल दलितों और अल्पसंख्यकों को ही भीड़ की हिंसा का शिकार बताते हुए इस सच को जानबूझकर ओझल किया गया कि अन्य अनेक वर्गों के लोग भी भीड़ के उन्माद की चपेट में आ रहे हैं। आखिर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सिक्के का एक ही पहलू दिखाना बौद्धिक बेईमानी नहीं तो और क्या है? वास्तव में इसी रवैये के कारण यह कहा जाने लगा है कि उदारवादी ही उदारवाद के सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं।

49 प्रबुद्ध लोगों ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि जय श्रीराम नारे को एक भड़काऊ नारे में तब्दील कर दिया गया है और उसके नाम पर भीड़ हिंसा कर रही है। इससे इन्कार नहीं कि ऐसे एक-दो मामले सामने आए हैं, लेकिन क्या इक्का-दुक्का मामलों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जय श्रीराम नारे का इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए किया जा रहा है? क्या इस सच की अनदेखी कर दी जाए कि जय श्रीराम नारे के नाम पर कथित हिंसा के कई मामले फर्जी भी पाए गए हैं? आखिर इन फर्जी घटनाओं को कौन गढ़ रहा है? निःसंदेह भीड़ की हिंसा पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है और इस जरूरत की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन यह साबित करने का कोई मतलब नहीं कि जय श्रीराम का नारा एक भड़काऊ नारा बन गया है। सदियों से राम का नाम अलग-अलग भाव में लिया जाता रहा है, जैसे सीताराम, सियाराम, राम-राम। इसी कड़ी में जय श्रीराम भी है। इसका उपयोग भक्तिभाव प्रकट करने के साथ ही जोश जगाने या फिर गर्व का भाव व्यक्त करने के लिए होता चला आ रहा है। साफ है कि जय श्रीराम नारे को भड़काऊ करार देना एक किस्म की असहिष्णुता ही है।

उद्योगों को बचाना जरूरी

बिजली बिल में वृद्धि से कोल्हान क्षेत्र की चार कंपनियों के बंद होने की स्थिति इस तथ्य को रेखांकित कर रही कि झारखंड में उद्योगों को बचाने-बढ़ाने के लिए सुनियोजित कार्ययोजना पर अमल करने की आवश्यकता है। उद्योगों के सामने यह समस्या सिर्फ कोल्हान में ही नहीं आई है। पूरे राज्य के छोटे-बड़े उद्योग बिजली दरों में हुए इजाफे से प्रभावित हैं। इसका असर दिखने भी लगा है। इसलिए समय रहते बिजली बिल की मार से उद्योगों को बचाने के लिए शासन के स्तर से ठोस पहल शीघ्र होनी चाहिए। ऐसा रास्ता तलाशा जाना चाहिए कि औद्योगिक विकास की गाड़ी बेपटरी न हो जाए। वैसे भी किसी उद्योग या कंपनी के बंद होने का प्रतिकूल असर चौतरफा होता है। कामगार एवं उनके परिवार तो सीधे तौर पर प्रभावित होते ही हैं, उद्योगों के आसपास के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी चपेट में आती है। राज्य की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि यह बात भी सही है कि केवल सब्सिडी और मदद के जरिए किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन इसे भी नहीं नकारा जा सकता कि ऐसी मदद छोटे उद्योगों के लिए संजीवनी साबित होती है। राज्य के वैसे उद्योगों को यह राहत तत्काल मिलने की दरकार है जो बिजली का अधिकतम उपयोग करके संचालित होते हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) के प्रस्ताव पर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) ने वर्ष 2019-20 के दौरान बिजली की दरों में औसतन छह फीसद की वृद्धि की है, जबकि फर्नेस वाले उद्योगों के लिए यह वृद्धि 24 फीसद तक है। स्वाभाविक तौर पर उन उद्योगों को बिजली दर वृद्धि बहुत भारी पड़ रही। इसलिए इस प्रस्ताव पर समग्र विचार मंथन कर ऐसी नीति अंगीकार की जानी चाहिए जिसमें स्पष्ट रहे कि किस श्रेणी के उद्योग को किस तरह से सब्सिडी दी जाएगी और कितने दिनों तक। इस क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सब्सिडी का बेजा फायदा उठाने की कोशिश न की जाए। बिजली चोरी करने या बिजली बिल का समय से भुगतान नहीं करने का रिकॉर्ड अपने नाम रखनेवाले उद्योगों को इस लाभ से हर हाल में वंचित रखने का भी इंतजाम होना चाहिए। तभी सही उद्योगों को सही तरीके से मदद मिल सकेगी और फर्जीवाड़ा करनेवाले उद्योगों को कार्रवाई का करंट लगेगा।

किसी उद्योग या कंपनी के बंद होने का प्रतिकूल असर चौतरफा होता है। कामगार एवं उनके परिवार तो सीधे तौर पर प्रभावित होते ही हैं, क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी चपेट में आती है

नजरअंदाज करने लायक बयान

हर्ष वी पंत

अगर ट्रंप के विचारों से तालमेल बैठाने में खुद उनके विदेश विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है तो समझा जा सकता है कि भारत के सामने यह कितनी बड़ी चुनौती है?

जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को लेकर भारत की परंपरागत नीति के उलट बयान दिया तो मानों भूचाल सा आ गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप ने अनपेक्षित और उससे भी कहीं अधिक नाटकीय रूप से यह दावा किया कि भारत ने उनसे कश्मीर मामले में मध्यस्थता की पेशकश की। उनके इस बयान से भारत में राजनीतिक हलचल होनी स्वाभाविक थी। उनका यह बयान सुर्खियां बन गया। जापान के ओसाका में आयोजित जी-20 देशों के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बातचीत का हवाला देते हुए ट्रंप ने बड़े विचित्र ढंग अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, 'दो सप्ताह पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ था और हमने इस विषय पर चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि क्या आप मध्यस्थ बनना चाहेंगे? मैंने पूछा कि कहां? उन्होंने जवाब दिया कश्मीर में। चूंकि यह मसला इतने वर्षों से उलझा हुआ है तो मुझे लगता है कि वे इसे सुलझाना चाहते हैं और आप (इमरान) भी इसका समाधान होते देखना चाहते हैं। अगर इसमें मैं कुछ मदद कर सकता हूं तो ऐसा करते हुए मुझे बेहद खुशी होगी।'

भारत में तमाम लोगों के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह अमेरिका की दशकों पुरानी उस नीति के उलट है जिसमें वह कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा मानता आया है कि यह मसला भारत और पाकिस्तान को आपस में सुलझाना चाहिए। उसका यह रवैया भारतीय भावनाओं के अनुरूप ही रहा। हालांकि बराक ओबामा सहित तमाम अमेरिकी राष्ट्रपति कश्मीर मसले पर मध्यस्थ बनने का मोह रोक नहीं पाए और यदाकदा ऐसी पेशकश करते रहे। हालांकि अब वाशिंगटन को भलीभांति समझ आ गया है कि अगर वह भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर और परिपक्व करना चाहता है तो फिर कश्मीर के मसले में टांग न ही अड़ाए तो बेहतर होगा। फिर भी आखिर ट्रंप को ऐसा कहने के लिए किसने उकसाया होगा, इस पर भारत में अटकलों का बाजार गर्म है। ट्रंप की इस हालिया जुमलेबाजी की तह में जाने के लिए तमाम परतें उघाड़ी जा सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि यह अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि अहम भू-राजनीतिक मसलों पर टिप्पणी करते हुए ट्रंप की क्या मनोदशा रहती है? अगर ट्रंप के विचारों से तालमेल बैठाने में खुद उनके विदेश विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है तो समझा जा सकता है कि भारत के सामने यह कितनी बड़ी चुनौती है?

चूंकि यह मसला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील था तो भारतीय पक्ष ने भी त्वरित और कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, 'हमने अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी देखी कि यदि भारत और पाकिस्तान अनुरोध करते हैं तो वह कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसा कोई निवेदन नहीं किया है। भारत का हमेशा से यही रुख रहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी किस्म के मुद्दों पर केवल द्विपक्षीय स्तर पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की सक्रियता से पहले जरूरी होगा कि वह अपने यहां आतंकी ढांचा खत्म करें। शिमला समझौते और लाहौर घोषणापत्र में वे सभी बिंदु हैं जिनके आधार पर सभी मुद्दे द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाए जा सकते हैं।'

अवधेश राजपूत

ट्रंप के बयान पर भारत की प्रतिक्रिया बहुत विस्तृत नहीं थी, लेकिन इसने यह जरूर स्पष्ट किया कि इस मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे थे। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया। नई दिल्ली की ओर से औपचारिक विरोध जताने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने भी नुकसान की कुछ भरपाई की कोशिश के तहत यह रेखांकित किया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है और अगर दोनों देश बातचीत के लिए साथ आते हैं तो अमेरिका इसका स्वागत करता है। उसने यह भी कहा कि आंतकवाद के खिलाफ पाकिस्तान 'निरंतर और स्थायी' कदम उठा रहा है जो भारत के साथ सार्थक वार्ता में अहम है।

कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा है और भारतीयों की अपने मित्र देशों से यह अपेक्षा सही है कि वे भारत के मूलभूत हितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं, मगर ट्रंप जैसे अक्खड़ नेता से यह अपेक्षा बेमानी लगती है। वह बहुत ही अस्थिर मिजाज वाले राष्ट्रपति हैं और उनका रवैया भी गैरपरंपरागत है। अमेरिका के कुछ करीबी देशों के प्रति उनके विषवमन ने अमेरिकी कूटनीतिज्ञों के समक्ष चुनौती बढ़ा दी है। ऐसे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय नई दिल्ली को कुछ प्रतीक्षा कर यह देखना चाहिए कि कश्मीर को लेकर ट्रंप के रवैये में आगे क्या रुझान देखने को मिलता है? अगर वह कश्मीर पर ऐसे ही हाव-भाव दिखाते हैं तो भारत को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, लेकिन अगर वह इस मसले पर आगे कुछ नहीं बोलते हैं तो फिर इसे कोई मुद्दा न मानते हुए इस पर ऊर्जा व्यर्थ करने का कोई अर्थ नहीं है। ध्यान रहे कि व्हाइट हाउस की ओर से ट्रंप-इमरान के संयुक्त बयान में कश्मीर का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ट्रंप के बयान पर भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया दमदार और दूसरे पक्ष को साधने की कवायद भी सराहनीय रही। अमेरिका को संदेश मिल गया होगा कि उसे भूल सुधार की दरकार है। वह यही करने में जुटा है। भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय एजेंडे में कई और मुद्दे सुलझाए जाने बाकी हैं। इनमें ईरान के साथ व्यापार, रूस के साथ एस 400 की खरीद से लेकर 5जी तक पर पेंच फंसे हुए हैं। वांछित परिणाम हासिल करने की दिशा में परस्पर सहमति के स्तर पर पहुंचने के लिए दोनों देशों को सार्थक संवाद की दरकार है। वास्तव में हमारे लिए अफगानिस्तान में बनते हालात गहन चिंता का विषय होने चाहिए, विशेषकर यह देखते हुए कि ट्रंप ने किस तरह अफगानिस्तान से निकलने में पाकिस्तान से मदद मांगी है।

वैश्विक स्तर पर कश्मीर मुद्दे की गूंज वक्त के साथ कुछ कमजोर पड़ी है, लेकिन भारतीय राजनीति के कुछ हलकों में इसकी व्यापक संवेदनशीलता को देखते हुए यह मुद्दा वापस वैश्विक एजेंडे में आ सकता है। अतीत में जब भारत वैश्विक शक्ति अनुक्रम में अपेक्षाकृत निचले पायदान पर था तब भी वह तमाम बड़ी शक्तियों को कश्मीर मामले में दखल देने से रोकने में सफल रहा था। उसकी तुलना में आज जब हम पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं तब कश्मीर के मुद्दे और बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम हैं। ट्रंप का अनर्गल बयान जिस लायक है उसे उसी लिहाज से नजरअंदाज करते हुए नई दिल्ली को अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

(लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

भाजपा के कांग्रेसीकरण का सवाल

प्रदीप सिंह

भाजपा और कांग्रेस में एक बुनियादी फर्क है और वह शायद हमेशा रहेगा तथा भाजपा के कांग्रेसीकरण को रोकेगा

राजनीतिक हलकों में आजकल यह नया विमर्श चल रहा है कि भाजपा कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है या फिर उसका कांग्रेसीकरण हो रहा है। पिछले दो महीने में जिस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में दूसरे दलों से सांसद, विधायक और नेता भाजपा में शामिल हुए या कराए गए उससे यह विमर्श निकला है। केंद्र के साथ 16 राज्यों में सत्ता में होने के बावजूद भाजपा को ऐसा करना क्यों जरूरी लग रहा है और इसके जरिये पार्टी अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे रही है? कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल-एस की साझा सरकार गिरने के बाद भाजपा की 17वीं राज्य सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके पहले गोवा में कांग्रेस के दस विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। अब चर्चा है कि अगला नंबर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का है। उसके बाद राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। इन अटकलों के आधार पर सवाल उठने लगा है कि क्या भाजपा 1960-70 के दशक की कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है? अपने वर्चस्व के दिनों में कांग्रेस ने भी अपनी विरोधी सरकारों के साथ यही किया था। एक समय गोविंदाचार्य ने भी कहा था कि भाजपा दरअसल गुलाबी छटा वाली कांग्रेस है।

भाजपा में इस समय दो धाराएं समानांतर रूप से चल रही हैं और यह ध्यान रहे कि समानांतर रेखाएं कभी मिलतीं नहीं। पहली धारा के तीन चरण हैं। पहला, ऐसे क्षेत्रों में जहां पार्टी का जनाधार नहीं है वहां दूसरे दलों से लोगों को पार्टी में शामिल करके पार्टी का यकायक विस्तार। इसकी शुरुआत 2014 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत के बाद हरियाणा से हो गई थी। जहां कांग्रेस के राज्य स्तर के कई नेता भाजापा में शामिल हो गए और राज्य में सरकार बन गई। इसके अलावा बंगाल, असम, केरल, तेलंगाना, आंध्र जैसे राज्यों में दूसरे दलों से लोगों को पार्टी में इसी रणनीति के तहत लाया गया। दूसरा, नए सामाजिक समूहों से पार्टी को जोड़ना। इसके लिए पार्टी ने अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देकर बड़े पैमाने पर इस वर्ग में अपनी पैठ बनाई। इसका नतीजा उत्तर प्रदेश के विधानसभा और हाल के लोकसभा चुनाव में दिखा। तीसरा, जहां कांटे की टक्कर है वहां कुछ विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाने का प्रयास। पार्टी की इसी नीति को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। गोवा में सरकार को स्थिर बनाने के लिए भाजपा ने विचारधारा और नैतिकता, दोनों स्तर पर समझौता किया। जिस नेता के बारे में पार्टी ने प्रचार किया कि वह दुराचारी है उसे पार्टी में शामिल किया और उसकी पत्नी को मंत्री बना दिया। गोवा में इस समय भाजपा के 27 विधायकों में से 15 ईसाई हैं यानी उनका बहुमत है। क्या गोवा भाजपा के लिए इतना बड़ा और अहम प्रदेश है कि उसके लिए पार्टी ऐसे समझौते करे? आंध्र के दागी नेता जिसे भाजपा राज्य का माल्या कहती थी, को इस आधार पर पार्टी में शामिल किया गया कि राज्यसभा में बहुमत जुटाने के लिए ऐसा करना मजबूरी थी।

कर्नाटक का मामला थोड़ा अलग है। राज्य में भाजपा का मजबूत जनाधार है। राज्य की 28 में से 25 सीटों पर उसके सांसद हैं। कांग्रेस और जद-एस के बागी विधायकों में से ज्यादातर बिल्डर हैं। अगले कुछ दिन में ये भाजपा में शामिल होंगे ही। राज्य में अभी जो हालात हैं उनमें जब भी विधानसभा चुनाव होते तो पार्टी को बहुमत मिलने की प्रबल संभावना थी। फिर जोड़तोड़ की सरकार बनाने का फैसला क्यों किया गया? विपक्ष के जो बागी आएंगे उनकी कितनी मांगे पार्टी पूरी कर पाएगी? ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व इन सवालों को महत्वहीन मानता है। आरएसएस में आजकल इन नवागंतुकों को नव नेकरवादी कहा जा रहा है। अभी तक कुछ अपवादों को छोड़कर नव नेकरवादियों को कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला है। यही दूसरी धारा का संकेत है। दूसरी बार केंद्र में सरकार बनने के बाद मेनका गांधी, जयंत सिन्हा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, सत्यपाल सिंह, केजे अल्फांस और राम कृपाल यादव जैसे कई नव नेकरवादियों की छुट्टी कर दी गई। जो बचे वे केवल अपनी कार्यकुशलता की वजह से। इसके जरिये पार्टी ने एक संदेश दिया है कि उसकी नजर में विचारधारा गौण नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठियों, एनआरसी, अनुच्छेद 370, 35 ए, समान नागरिक संहिता और तीन तलाक के मुद्दे पर पार्टी कायम है। अमित शाह का गृहमंत्री बनना भाजपा की विचारधारा के लिहाज से सामान्य घटना नहीं है। जो काम पिछले पांच साल में नहीं हुआ वह अब होगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अमित शाह की कश्मीर यात्रा के दौरान जो नजारा देखने को मिला वह आने वाले दिनों का संकेत है। इस मोर्चे पर मोदी-शाह की जोड़ी ने एक और बड़ा और शायद सबसे अहम काम किया है और वह है वाजपेयी सरकार के दौरान हुई गलतियों से सबक सीखकर आरएसएस, पार्टी और सरकार में सांगोपांग समन्वय। कर्नाटक के बीएल संतोष का संगठन महासचिव बनना इस रणनीति के अलावा एक और संदेश है कि वाजपेयी राज में जिस तरह संगठन की उपेक्षा हुई थी वैसा नहीं होगा। उस समय वाजपेयी, आडवाणी दोनों के सरकार में जाने के बाद ऐसा ही हुआ था। संगठन की दृष्टि से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यह सबसे अहम बदलाव है।

भाजपा कांग्रेस तभी बन सकती है जब नव नेकरवादी दूध में पानी के बजाय पानी में दूध की तरह हो जाएं। इसकी संभावना फिलहाल तो नजर नहीं आती यानी दोनों धाराओं का मिलन मुश्किल है। भाजपा और कांग्रेस में एक बुनियादी फर्क है, जो शायद हमेशा रहेगा। भाजपा में विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की एक फौज हमेशा रहती है। ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की सप्लाई लाइन संघ से सदा बनी रहती है। जब भाजपा विचारधारा से हटकर सत्ता के लिए ही सब कुछ करने की ओर बढ़ती है तो कार्यकर्ताओं की यह फौज घर बैठ जाती है। उसके बाद चुनाव में जो होता है उससे सत्ता का नशा उतर जाता है। कभी-कभी नेताओं को गलतफहमी हो जाती है कि कार्यकर्ताओं की निष्ठा विचारधारा से ज्यादा उनके प्रति है। बड़े-बड़े दिग्गज इसी मुगालते में हाशिये पर चले गए। कार्यकर्ताओं का यही निष्ठा भाव ही भाजपा को कांग्रेस नहीं बनने देगा।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समस्या से मुक्ति

हर व्यक्ति समस्याग्रस्त है, उसके समाधान के लिए जरूरी है कि हम अपनी समस्या को समझें और फिर समाधान खोजें। मानसिक बल निषेधात्मक भावों द्वारा कमजोर होता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह माना है कि जितने नकारात्मक भाव हैं, वे हमारी बीमारियों एवं समस्याओं से लड़ने की प्रणाली को कमजोर बनाते हैं। ईर्ष्या, भय, क्रोध, घृणा नकारात्मक भाव हैं। प्रायः यह कहा जाता रहा है कि ईर्ष्या मत करो, घृणा और द्वेष मत करो। इससे पाप कर्म का बोध होता है। एक धार्मिक के लिए यह महत्वपूर्ण निर्देश है, किंतु आज यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गया है। विज्ञान ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, उसे निषेधात्मक भावों से बचना चाहिए। बार-बार क्रोध करना, चिड़चिड़ापन आना, मूड का बिगड़ते रहना-ये सारे भाव हमारी समस्याओं से लड़ने की शक्ति को कम करते हैं।

आज जरूरत है कि हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए औरों के मोहताज न बनें। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे भीतर से न मिले। भगवान महावीर का यह संदेश जन-जन के लिए सीख बने-'पुरुष! तू स्वयं अपना भाग्यविधाता है।' औरों के सहारे मुकाम तक पहुंच भी गए तो क्या? इस तरह की मंजिलें स्थायी नहीं होतीं और न इस तरह का समाधान कारगर होता है। हमारे भीतर ऐसी शक्तियां हैं, जो हमें बचा सकती हैं। संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्पवान व्यक्ति अंधकार को चीरता हुआ स्वयं प्रकाश बन जाता है। चंचलता की अवस्था में संकल्प का प्रयोग उतना सफल नहीं होता जितना वह एकाग्रता की अवस्था में होता है। हर व्यक्ति रात्रि के समय सोने से पहले एक संकल्प करे, उसे पांच-दस मिनट तक दोहराए, मैं यह करना या होना चाहता हूं, इस भावना से स्वयं को भावित करे, एक निश्चित भाषा बनाए और उसकी सघन एकाग्रता से आवृत्ति करे, ऐसा करने से संकल्प बहुत शीघ्र सफल होता है। व्यक्ति में यह आत्मविश्वास पैदा हो जाए कि जो मुझे चाहिए वह मेरे भीतर है तो मानना चाहिए कि समस्या के समाधान का मार्ग मिल गया है। इस प्रकार से शक्ति का बोध, जागरण की साधना और उसका सही दिशा में नियोजन, यदि इतना सा विवेक जाग जाए तो सफलता का स्रोत खुल जाएगा।

ललित गर्ग

विज्ञान की दुनिया में महिलाएं

डॉ. मोनिका शर्मा

देश में विज्ञान के क्षेत्र में स्त्रियों की बढ़ती भागीदारी सामाजिक-पारिवारिक स्तर में भी बड़ा बदलाव ला सकती है

हाल ही में सफलतापूर्वक लांच किए गए चंद्रयान-2 अभियान में इसरो की दो महिला वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अपने देश के सपनों को आकार देने वाले चंद्रयान-2 प्रोजेक्ट में ऋतु करिधाल अभियान निदेशक और एम. वनिता परियोजना निदेशक हैं। सुखद है कि भारत का अंतरिक्ष में फतेह पाने का यह सिलसिला विज्ञान की दुनिया में देश की आधी आबादी की भूमिका भी पुख्ता कर रहा है।

यह सकारात्मक और संबल देने वाली बात है कि कभी महिलाओं का न के बराबर दखल वाले इस क्षेत्र में स्त्रियों का हर अभियान में बढ़-चढ़ योगदान देखने को मिल रहा है। विज्ञान क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करने के लिए अपेक्षित भी है कि महिला वैज्ञानिकों को ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने और खुद को साबित करने का अवसर मिले, ताकि राष्ट्र निर्माण से जुड़े एक अहम क्षेत्र में लैंगिक समानता लाने का माहौल बने। यकीनन इसरो का हर अभियान महिलाओं के विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान की दुनिया में बढ़ते कदमों का मजबूत आधार तैयार कर रहा है। इस बुनियाद पर आने वाले समय में देश की बेटियां विज्ञान और अनुसंधान जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में आगे बढ़ने की राह चुनेंगी। निःसंदेह महिला वैज्ञानिकों की यह भागीदारी इस क्षेत्र में युवतियों को मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने वाली है। फिलहाल यह संतोषजनक है कि देश के प्रमुख वैज्ञानिक अभियानों में शीर्ष स्तर से लेकर एक सफल टीम बनाने तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिखने लगा है।

इसरो की 2018-2019 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 2069 महिलाएं विज्ञान संबंधी तथा तकनीकी श्रेणियों और 3285 महिलाएं प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनुसंधान और विकास गतिविधियों में कार्यरत कुल 2.82 लाख लोगों में से 14 प्रतिशत महिलाएं हैं। समय के साथ इस हिस्सेदारी के आंकड़ों में हो रही बढ़ोतरी महिलाओं के जीवन के दूसरे पहलुओं को भी बेहतर बनाने वाला है। विज्ञान के क्षेत्र में स्त्रियों की बढ़ती भागीदारी सामाजिक-पारिवारिक स्तर में भी बड़ा बदलाव ला सकती है। वैज्ञानिक चेतना और तकनीकी जागरूकता स्त्री जीवन से जुड़ी कई रूढ़ियों से मुक्ति दिला सकती है।

आज जिंदगी के हर मोर्चे पर महिलाएं बराबरी से शामिल हैं। खेल का मैदान हो, राजनीति का अखाड़ा हो या फिर अंतरिक्ष से जुड़े अनुसंधान की दुनिया। हालांकि हमारे यहां कई कारणों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं की संख्या कम रही है। यही वजह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को कम करने और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रशासनिक ही नहीं, सामाजिक-पारिवारिक स्तर पर भी सहयोगी वातावरण बनाना जरूरी है, ताकि बड़ी संख्या में युवा महिलाएं विज्ञान की दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकें। सुखद है कि इस मोर्चे पर भी धीरे-धीरे स्थिति बदल रही है। विज्ञान और अनुसंधान की दुनिया में न केवल महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है, बल्कि वे नेतृत्वकारी भूमिका में भी अपना अहम योगदान दे रही हैं।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

आरटीआइ कानून में संशोधन

सूचना कानून पर मंडराता खतरा शीर्षक से लिखे अपने लेख में जगदीप एस छोकर ने मोदी सरकार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम में किए जा रहे संशोधन को जनहित के विरुद्ध बताया है, लेकिन जरूरी नहीं कि मोदी सरकार अगर सूचना कानून में कुछ संशोधन करके सभी अधिकार अपने अधीन ले लेती है तो इससे आम लोगों को नुकसान ही होगा। हो सकता है कि मोदी सरकार इस कानून को और सरल और इसकी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही हो। वैसे भी कानून की धारा-9 में कुछ मामलों में सूचना नहीं देने का आधार है। धारा-11 के तहत थर्ड पार्टी से संबंधित जानकारी नहीं देने का भी प्रावधान है। वहीं धारा-24 के तहत कानून कुछ संगठनों पर लागू भी नहीं होता है। ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि यह अधिनियम सूचना देने में शत प्रतिशत सक्षम है। सभी सरकारी विभाग सरकार के अधीन ही होते हैं। ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि जो मौजूदा समय में सूचना अधिकार नियम के अंतर्गत सूचनाएं दी जाती हैं, वे सरकार की मर्जी के खिलाफ ही दी जाती हैं? अक्सर कभी-कभी कुछ विभाग इस कानून में मांगी कुछ जानकारियों को न देने के लिए यह तर्क भी दे देते हैं कि यह जानकारी गोपनीयता से जुड़ी है। हमारे देश में बहुत से लोग तो सूचना अधिकार अधिनियम से भी अनजान हैं। उन्हें इसके प्रति जागरूक करने के लिए सरकारें भी गंभीरता नहीं दिखातीं। शायद वे अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहतीं। अगर देश के सभी नागरिक इस अधिनियम के प्रति जागरूक हो गए तो फिर भ्रष्ट नेताओं-अधिकारियों की खैर नहीं। देश के बुद्धिजीवी वर्ग को चाहिए कि वह लोगों को इसके प्रति जागरूक करे।

raju09023693142@gmail.com

मेलबाक्स

होनहार हिमा दास

हिमा दास भले ही मुंह में चांदी का चम्मच लिए न पैदा हुई हों, पैरों से सोना रोंदने की काबलियत रखती हैं। देश जहां बेटियों की सुरक्षा के लिए फिक्रमंद है वहीं हिमा बेफिक्री से दुनिया को पैरों से नापने चल पड़ी हैं। एक पखवाड़े में छह गोल्ड मेडल झटकना कोई बच्चों का खेल नहीं। मगर हिमा मल्लिका-ए-रफ्तार ने खेल-खेल में यह कारनामा कर दिखाया। उम्मीद है कि इस होनहार धावक की रफ्तार कभी कम न होगी।

mkmishra75@yahoo.in

कर्नाटक में बना इतिहास

पिछले साल मई 2018 में जब येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और राज्यपाल ने उन्हें 4 दिन का समय बहुमत साबित करने के लिए दिया था तो आधी रात को कोर्ट ने आदेश दिया था कि 24 घंटे में बहुमत सिद्ध किया जाए। न्यायमूर्ति ने कहा था कि जिसे सदन का विश्वास प्राप्त नहीं, उसे एक घंटे भी पद पर बने रहने का हक नहीं है। इस वर्ष पूरे 6 दिन एक अल्पमत की सरकार शासन करती रही। यह शायद भारतीय इतिहास की पहली घटना है, जब इतने दिन तक विश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई चलती रही। दो-दो बार राज्यपाल का आदेश ठुकराते हुए मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहे, ये एक खतरनाक नजीर बनी है।

ajay.mittal97khandak@gmail.com

आत्मनिर्भरता की उड़ान

चंद्रयान-2 भारत की बड़ी सफलता है। भारतीय वैज्ञानिकों को चाहिए कि इसी तरह आधुनिक हथियार भी बनाएं, जिससे पश्चिमी देशों से हथियार खरीदने पर अधिक धनराशि खर्च न करनी पड़े।

डॉ. नूतन कुमार सी. पाटणी, नोएडा

ट्रंप का अनुचित बयान

दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति अगर झूठ बोलें तो सबके सामने उनकी छवि कैसी बनेगी? यह सोचने की बात है। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि उन्हें समझ नहीं है। हो सकता है वह किसी रणनीति के तहत ऐसा बोलते हों। कश्मीर मसले पर उनके दो कारण हो सकते हैं। एक भारत का रूस से अत्याधुनिक हथियार खरीदना और दूसरा पाकिस्तान की मदद से तालिबान से वार्ता कर अफगानिस्तान से शांतिपूर्ण तरीके से अमेरिकी सेना को बाहर निकालना। लेकिन इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगना कतई उचित नहीं है। सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया है, वह काफी है। अमेरिका खुद भी न तो इस बयान का समर्थन कर रहा है और न ही किसी रिकार्ड में रखा है। ऐसे में बेवजह का शोर शराबा करना गलत है।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।